are more than 250 public sector undertakings. From Rs. 29 crores investment in the year

3.00 P.M.

1951, it has gone beyond Rs. 70,000 crores now. The return on this investment is very low, negligibly low. Therefore, this House, the people and the industry are naturally anxious to know the full picture of the working of the public sector industries. We have to know the physical, financial and socio-economic performance of these enterprises. Therefore, I would urge upon the Government not to delay but to bring forward a White Paper giving a comprehensive, integrated view, of the performance of the Public sector undertakings. That is necessary to avoid not only misgivings which are operating in certain quarters but also to provide a new thrust for public sector industries, to identify the problems faced by them — how far these industries are run on healthier lines, how far these industries are realising the objectives for which have been started. I do not want to go into various objectives for which the public sector undertakings have been started but let me say finally, the country needs to know the state of affairs in the public sector and its performance, how the public sector has been able to help the growth of industrialisation in the country and also how far the public sector helped us to realise the social objectives which have been enunciated. Therefore, I reiterate my demand that the Government should not dilly-dally on this question. They should come forward with a White Paper as early as possible.

Bomb Blasts in Kashmir Valley

श्री धर्मपाल (जम्मू और काश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जम्मू-काश्मीर में स्थिति चिन्ताजनक है और सारे देशवासियों को इसकी चिन्ता है। जम्मू-काश्मीर रियासत टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। लेकिन वहां पर जो वायलेन्स के वाकयात हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, उससे कानून को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। अप्रैल और मई के दो महीनों में जब कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां जाते हैं तब यह स्थिति हो रही है। पाकिस्तान से ट्रेन्डशुदा नवजवान जिनकी संख्या तीन सौ के लगभग है, कुछ तो रियासत में दाखिल हो गये हैं और कुछ होने वाले हैं। एक सौ के करीब हमारी सक्यूरिटी फोर्सेज ने पकड़े हैं और माह जनवरी से बम ब्लास्ट और वायलेन्स के काफी वाकयात वहां हुए हैं और अब दो दिन पहले, ईद के दिन, 8 और 9 मई को हुए हैं। 8 मई को चार बम धमाके हुए, काश्मीर में दो और दो अनंतनाग में हुए। एक बम धमाका तो डिप्टी कमिश्नर की रिहायश पर हुआ जिससे मकान की दीवारें और खिड़कियों को नुक्सान हुआ दूसरा बम धमाका एक सिनेमा के बाहर हुआ जिससे बुकिंग काउन्टर और दीवार को नुकसान हुआ। अनंतनाग में जो बम धमाका हुआ वह मोबाइल मजिस्ट्रेट के दफतर के बाहर हुआ जिससे पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। कल जो बम धमाका हुआ वह काश्मीर के लाल चौक पर जहां पर एक डबल डेकर बस थी उसमें हुआ जिसमें एक मुलाजिम, मैनेजर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का हलाक हुआ और छः लोग जख्मी हुए। ये जो काश्मीर लिबेशन फ्रन्ट और पिपूल्स लीग एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट हैं, ये काश्मीर के नवजवानों को गुमराह करके पाकिस्तान और काश्मीर में भेज रहे हैं और वे वहां से ट्रेनिंग और जदीद हथियार लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेन्स विंग है वह भी उन्हें मदद कर रही है। और इन्टेरोगेशन से इस बात का पता चला है कि पैसे और हथियार देकर उन्हें भेजते हैं ताकि वे तोड़-फोड़ करें और ऐसे हालात वहां पर पैदा हों जिससे अमन दरमवरम हो। यह कोई छोटी मोटी साजिश नहीं। यह चलती है चाहे सिख एक्स्ट्रीमिस्ट हो, चाहे मुजाहदीन, हो वे काश्मीर के लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। लंदन मे जो कांफ्रेंस हुई है उसमें जगजीत सिंह चौहान ने जहां खालिस्तान की बात कही वहां मुजाहदीन के रिप्रजन्टेटिव्स भी थे और काश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग भी थे। यह देखना

[श्री धर्मपाल]

हमारा होम मिनिस्ट्री का काम है और उसको अपनी एजेंसियों को सतर्क करना चाहिए कि ये जो ट्रेंड होकर दाखिल हो जाते हैं उनको यहां आना बंद किया जाय। एक ऐक्शन प्लान जो जम्मू काश्मीर के चीफ मिनिस्टर और वहां के अधिकारियों से मिलकर होम मिनिस्ट्री ने बनाया हैं उस पर अमल हो और जो भी मदद काश्मीर सरकार चाहती है, सेक्युरिटी फोर्सेज की, इंटेलीजेंस की सेवायें जो वे चाहते हैं वह काश्मीर सरकार को दी जाय। जम्मू काश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारुख अब्दुल्ला ने बड़े जोर से कहा है कि वह इंतहा पसंदों का खात्मा करेंगे और आईनो हाथों से अगर जरुरत पड़ेगी तो घर घर की तलाशी लेंगे और एक्स्ट्रीमिस्ट का खात्मा करेंगे। इससे बड़ा होसला बनता है। मरकजी सरकार को वहां की सरकार की मदद करनी चाहिए ताकि टूरिस्म का सीजन वहां है वहां लोग जा सकें और वहां की सादियात पर अच्छा असर पड़े।

Growing violence in Jharkhand Agitation

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि बिहार राज्य बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य है और उसका एक खासा हिस्सा है जो कि छोटा नागपुर और संथाल परगने का है। यह इलाका बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वहां पर आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है। वे लोग हमारी सरकार से बहुत ही नाराज हैं क्योंकि उनकी बड़ी उपेक्षा हुई है। 40 वर्ष की आजादी के बाद भी सरकार उनके लिये कुछ कर नहीं सकी है। वे लोग वह पृथक राज्य के लिये बराबर आंदोलन करते रहे हैं, जो झारखंड आंदोलन के नाम से देश में जाना जाता है। सरकार ने उनकी मांग पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है। नतीजा यह हुआ है कि हाल के आंदोलन में छोटा नागपुर में जो झारखंड बंद का ऐलान किया था उसमें रेल की पटरियां तोड़ी गई और कई जगहों पर हिंसात्मक वारदातें हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि यह आंदोलन हिंसा की ओर जा रहा है। वसे स्वयं सरकार जब तक तोड़-फोड़ नहीं होगी, हंगामा नहीं होगा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर अकल की बात हम लोग करना चाहें तो यहां इसकी इजाजत नहीं। आप भी घंटी बजा देते हैं और वे जबर्दस्त घंटा बजा देते हैं सुनते ही नहीं हैं हमारी बात। इसलिये ये हिंसात्मक कार्यवाहियां बढ़ती जा रही हैं। उनकी बहुत सी मांगे जायज हैं। उस क्षेत्र में औद्योगीकरण हुआ है, बड़े बड़े कल-कारखाने खुले हैं और आदिवासी लोगों को अपने घर से निकाल दिया है। इस कारण वे जगह-जगह मारे-मारे फिर रहे हैं, बहुत सी उनकी दिक्कते हैं। इसलिये सरकार उनकी समस्याओं पर विचार करे। हमारे संविधान में षष्ठम अनुसूची, सिक्स्थ शैड्यूल है, फिर अनुच्छेद, आर्टिकल 371 है, जिसके आधार पर अभी आपको अनुभव हुआ और गोरखालैंड आंदोलन के परिणामस्वरूप आपने वहां पर परिषद बनाई है। इन बातों को देखते हुए उनके साथ बातचीत की जानी चाहिए जिससे कि वहां पर हिंसात्मक कार्यवाहियां न बढ़ें। आपको उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में जल्दी से जल्दी सरकार कार्यवाही करे जिससे एक ऐसा वातावरण बने ताकि हम लोग समस्या के निदान की ओर बढ़ सकें, यही मेरा अनुरोध है। मैं समझता हूं कि सरकार अवश्य इस ओर ध्यान देगी और वह और भी ज्यादा हिंसा का इंतजार नहीं करेगी ऐसा मेरा ख्याल है। लकिन होगा वही जो हिंसात्मक आंदोलन के जरिये होता है। शायद वही होगा। लेकिन मैं पुन: आपके जरिये सरकार से अपील करता हूं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे।

Problems faced by Onion growers in Gujarat

श्री रामसिंह राठवा (गुजरात): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात में तीन साल से सूखे के बाद इस वर्ष प्याज की अच्छी फसल हुई है। मगर आर्थिक दृष्टि से किसानों के लिए एक बार फिर यह सूखे का वर्ष साबित हुआ है। अच्छी फसल होने की वजह से प्याज के दाम थोक बाजार में बहुत ज्यादा गिर गये हैं। किसानों को उसे मंडी तक ले जाने में जो उसका खर्चा लगता है कई बार उससे भी कम मिलता है।